

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी- अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 10.07.2019

निगरानी संख्या : 30/2019  
GCMS NO. : 2019/00019

सुरेन्द्र कुमार पुत्र हनुमान जाति जाट साकिन भोजेवाला तहसील सूरतगढ़

निगरानीकर्ता

बनाम

1. लूणसिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत निवासी भोजेवाला तहसील सूरतगढ़
2. प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति, पंचायत समिति सूरतगढ़ जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति, सूरतगढ़
3. ग्राम पंचायत सोमासर, जरिये सरपंच
4. ग्राम पंचायत भोजेवाला, जरिये सरपंच

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 97 व 92 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपरिथत-

1. श्री शिशपाल शर्मा, अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री संजय सैन व श्री सुभाष बिश्नोई अधिवक्तागण गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 व 4

:: निर्णय ::

4-1-23  
दिनांक : 24.12.2022

निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता ने प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति, पंचायत समिति सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 21.10.2014 के प्रस्ताव संख्या 13 के विरुद्ध यह निगरानी पेश कर निवेदन किया कि गांव भोजेवाला की आबादी भूमि में प्रार्थी का पैतृक रिहायशी मकान पैमूदा 150 फुट गुणा 125 फुट स्थित है। प्रार्थी का इस रिहायशी अहाता/मकान पर पैतृक कब्जा पिछले 100 वर्षों से है जिस पर प्रार्थी के दादा/पड़दादा के रिहायशी मकान बने हुए थे आज से करीब 15/20 वर्ष पहले प्रार्थी का परिवार इस आबादी से चिपते खेत में अस्थायी ढाणी बनाकर रहने लग गये, इसलिये इस अहाते में बनाये हुये मकान धीरे-धीरे टूट गये व प्रार्थी इस आहाते का उपयोग नीरा तुड़ी डालने व पालतु जानवर गाय, भैस, भेड़ बकरी रखने में उपयोग करने लग गया। आज से तीस वर्ष पूर्व जब प्रार्थी का परिवार इस प्लाट में निवास करते थे तब ग्राम पंचायत सोमासर लगती थी व इन प्लाटों का विनिमितीकरण करके तत्कालीन ग्राम पंचायत सोमासर ने पट्टा बनाने की तमाम विधी सम्मत कार्यवाही करके गौका रिपोर्ट तीन पंचों की लेकर, आपति नोटिस जारी करके किसी भी व्यक्ति की आपत्ति ना पेश होने पर पंचायत समिति सूरतगढ़ द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 25.04.1989 की अनुपालना में दिनांक 30.03.1991 को राशि जमा करवाकर प्रार्थी के नाम की मिसल संख्या 363 पर पट्टा न 363 जारी कर दिया। उक्त पट्टे के विरुद्ध रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने पंचायत समिति सूरतगढ़ में एक शिकायत प्रार्थना पत्र/अपील पेश की, जिस पर रेस्पोंडेंट संख्या 2 ने बिना निगरानीकर्ता को सुने पुर्णतया एक तरफा निर्णय करके प्रार्थी के भाई व प्रार्थी के चचेरे भाईयो के तमाम पट्टे दिनांक 19.08.2011 को खारीज कर दिये। उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रार्थी ने इसी न्यायालय में निगरानी पेश की थी, जो दिनांक 14.08.2012 को स्वीकार की जाकर पंचायत समिति, सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 19.08.2011 निरस्त कर प्रार्थी को सुनवाई का मौका देकर विधिक प्रावधानों के आलोक में पुनः निर्णय पारित करने हेतु पंचायत समिति, सूरतगढ़ की प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति को प्रतिप्रेषित कर दी गई। परन्तु मातहत न्यायालय ने इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.08.2012 में दिये गये निर्देशों की पालना किये बिना ही सभी पट्टों के विरुद्ध एक ही अपील पेश होने पर भी उक्त अपील पर कार्यवाही करते हुए प्लाटों का गौका निरीक्षण किये बिना, पट्टों संबंधित पत्रावली तलब किये बिना तथा पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना, पक्षकारान की पीठ के पीछे निर्णय पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की पालना किये बिना ही पारित किया होने से निरस्त किया जाये।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। निगरानीकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा हाजिर हुए। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 बावजूद पर्याप्त सूचना के अनुपस्थित रहे। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 विकास अधिकारी की ओर से कोई हाजिर नहीं। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय सैन एवं सुभाष बिश्नोई हाजिर आये। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति उपलब्ध होने पर प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
सूरतगढ़ जिला-श्री गंगानगर



सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर अधिवक्ता निगरानीकर्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जैर निगरानी आदेश निगरानीकर्ता की पीठ के पीछे पारित करके प्रार्थी का रिहायशी मकान का पट्टा प्रार्थी को बिना सुने विधि विरुद्ध रूप से खारिज कर दिया। जैर निगरानी आदेश की जानकारी निगरानीकर्ता को कतई नहीं थी। दिनांक 04.07.2019 को उत्तरवादी न 4 ने धमकी दी कि निगरानीकर्ता इस प्लॉट से अपना कब्जा हटा लेये क्योंकि निगरानीकर्ता का पट्टा पंचायत समिति ने खारिज कर दिया है। निगरानीकर्ता ने उसी दिन पंचायत समिति में सम्पर्क किया तब निगरानीकर्ता को जैर निगरानी आदेश की जानकारी हुई। जानकारी होते ही बिना किसी देरी के निगरानी पेश कर दी गई। हस्तगत निगरानी जानकारी से अन्दर मियाद है। अतः मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि मातहत न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध निगरानी पेश करने में हुई देरी माफ की जाकर निगरानी अन्दर मियाद शुमार करने के आदेश प्रदान करे।

निगरानीकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का गैरनिगरानीकर्तागण द्वारा ना तो कोई प्रति शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया तथा ना ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया। दौराने बहस भी कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय गुणावगुण के आधार पर किया जाना सुक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा निगरानी अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

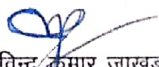
अपील में गुणावगुण पर बहस प्रस्तुत करते हुए अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने अपील मीमों के तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण संख्या 112/2011 अनवान सुरेन्द्र पुत्र हनुमान बनाम लूणसिंह आदि में पारित निर्णय दिनांक 14.08.2012 के पैरा संख्या 6 के बिन्दु संख्या 1 से 9 में वर्णित निर्देशों की पालना किये बगैर ही अधिनस्थ न्यायालय ने निगरानीकर्ता के नाम का पट्टा दिनांक 21.10.2014 को निरस्त कर दिया है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 3 ता 4 ने दौराने बहस निगरानी स्वीकार करने में अपनी सहमति प्रदान की।

उभय पक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। यह तथ्य सही है कि प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति, पंचायत समिति, सूरतगढ़ ने पूर्व में दिनांक 19.8.2011 को निगरानीकर्ता का पट्टा खारिज कर दिया था, जिसके विरुद्ध निगरानीकर्ता ने इस न्यायालय में एक निगरानी संख्या 112/2011 अनवान सुरेन्द्र बनाम लूणसिंह आदि पेश की जो दिनांक 14.08.2012 को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जाकर प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति, पंचायत समिति, सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 19.08.2011 निरस्त कर निर्णय के पैरा संख्या 6 में अंकित तथ्यों व विधिक प्रावधानों के आलोक में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति, पंचायत समिति, सूरतगढ़ को प्रतिप्रेषित किया गया था। जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली मुरतीब करके उभय पक्ष को सुनवाई की जाकर पूर्व में पारित निर्णय के पैरा संख्या 6 में वर्णित तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों की पालना करनी थी। परन्तु प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति, पंचायत समिति, सूरतगढ़ ने निर्देशों की पालना किये बिना ही सीधा ही जैर निगरानी आदेश दिनांक 21.10.2014 निगरानीकर्ता को सुने बिना पारित कर दिया जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है। इसके अतिरिक्त प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति, पंचायत समिति सूरतगढ़ ने निगरानीधीन प्रस्ताव लिखते समय निगरानीकर्ता का पट्टा संख्या भी 363 के स्थान पर 207 निर्णय दिनांक 25.7.1989 अंकित किया है, जबकि निगरानीकर्ता का पट्टा संख्या 363 है जो दिनांक 30.03.1991 को राशि जमा होने पर ग्राम पंचायत सोमासर द्वारा निगरानीकर्ता के पक्ष में जारी किया गया है। इस प्रकार प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति, पंचायत समिति, सूरतगढ़ का त्रुटिपूर्ण होने से हम निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार करना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर प्रशासन एवं स्थायी स्थापना समिति, पंचायत समिति सूरतगढ़ की बैठक दिनांक 21.10.2014 में पारित प्रस्ताव संख्या 14 (जिसके द्वारा निगरानीकर्ता का पट्टा संख्या 363 दिनांक 30.03.1991 निरस्त किया है), एतद्वारा अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण प्रशासन एवं स्थायी स्थापना समिति, पंचायत समिति सूरतगढ़ को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि इस न्यायालय की निगरानी संख्या 112/2011 अनवान सुरेन्द्र बनाम लूणसिंह आदि में पारित निर्णय दिनांक 14.08.2012 के पैरा संख्या 6 में दिये गये निर्देशों की पालना करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली बाद तुरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(अरविन्द कुमार जाखड)  
अतिरिक्त जिला क्लर्क  
सूरतगढ़ सूरतगढ़ नगर